

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9091/2026
CNR: RJHC020553822026 | URN: CRLMB / 16649U / 2026

Raisingh Alias Ramu Banjara S/o Bihari Lal Banjara, Aged About
45 Years, Resident of Lasadiya, Police Station Pander, District
Bhilwara (Raj.)

(At present confined in central Jail, Kota (Raj.))

-----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashvin Garg, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Shreeram Dhakad, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

06/08/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना जीआरपी कोटा, जिला जीआरपी अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 218/2016, अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सहअभियुक्त समीजुद्दीन को मादक पदार्थ अफीम की आपूर्ति करने के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध मादक पदार्थ के अपराध से संबंधित अन्य कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.05.2026 से अभिरक्षा में

चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने मुख्य अभियुक्त समीजुद्दीन को 04 किलो 500 ग्राम वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा के अवैध मादक पदार्थ अफीम की आपूर्ति की है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में अन्य आपराधिक प्रकरण मुकदमा नम्बर 222/2013, पुलिस थाना कोतवाली, भीलवाड़ा में अपराध अन्तर्गत धारा 4/6 आर.एन.सी. एक्ट का दर्ज हुआ है, जिसमें उसे दोषसिद्ध कर उस पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सहअभियुक्त समीजुद्दीन को 04 किलो 500 ग्राम वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा के अवैध मादक पदार्थ अफीम की आपूर्ति करने के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एक अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज रहा है, जिसमें उसे दोषसिद्ध कर उस पर जुर्माना लगाया गया है। इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा के मादक पदार्थ की आपूर्ति नहीं की हो, ऐसे में इस प्रकरण में धारा 37 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं।

मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा को कब्जे में रखना, उसका परिवहन करना या तस्करी करना एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 (जिसे आगे अधिनियम, 1985 कहा जाएगा) की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार अत्यंत गंभीर बताया गया है। अधिनियम, 1985 की धारा 37 को यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगा:—

[37. Offences to be cognizable and non-bailable.-- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),--

- (a) every offence punishable under this Act shall be cognizable;
- (b) no person accused of an offence punishable for¹[offences under section 19 or section 24 or section 27A and also for offences involving commercial quantity] shall be released on bail or on his own bond unless--
 - (i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and
 - (ii) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.
- (2) The limitations on granting of bail specified in clause (b) of sub-section (1) are in addition to the limitations under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or any other law for the time being in force on granting of bail.].

अधिनियम, 1985 की धारा 37 के अंतर्गत जो व्यक्ति वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा के मादक पदार्थ का क्रय-विक्रय करने के दंडनीय अपराध को करता है तो उसे तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक विद्वान लोक अभियोजक को अभियुक्त के जमानत लिए जाने के प्रार्थना पत्र पर विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो और जहां विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र को लिए जाने के संबंध में विरोध किया हो, तथा न्यायालय यदि ऐसे आधारों से संतुष्ट है, जिसके आधार पर वह यह पाता हो कि अभियुक्त ने अपराध कारित नहीं किया है और उसके द्वारा अन्य कोई अपराध कारित नहीं किया जाएगा। अधिनियम, 1985 की धारा 37(1)(बी) के तहत वाणिज्यिक मात्रा के मादक पदार्थों के अपराध के संबंध में जमानत लिए जाने के प्रति न्यायालय को नकारात्मक रुख अपनाने के लिए कहा गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित विनिश्चय "**Union of India Vs. Ajay Kumar Singh Alias Pappu; 2023 SCC OnLine SC 346**" के सुसंगत भाग को यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगा:—

"14. This apart, it is noticed that the High Court, in passing the impugned order of bail, had lost sight of Section 37 of the NDPS Act, which, inter alia, provides that no person accused of an offence involving commercial quantity shall be released on bail unless the twin conditions laid down therein are satisfied, namely, (i) the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the bail

application; and (ii) the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such an offence and that he is not likely to commit any such offence while on bail.

15. *For the sake of convenience Section 37(1) is reproduced hereinbelow:—*

“37. Offences to be cognizable and nonbailable.-

(1) Notwithstanding anything contained in the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)-

(a) every offence punishable under this Act shall be cognizable;

(b) no person accused of an offence punishable for 2[offences under section 19 or section 24 or section 27A and also for offences involving commercial quantity] shall be released on bail or on his own bond unless-

(i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and

(ii) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.”

16. *In view of the above provisions, it is implicit that no person accused of an offence involving trade in commercial quantity of narcotics is liable to be released on bail unless the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such an offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.”*

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित विनिश्चय "**State of Punjab Versus Balraj Singh @ Billa**; 2023 INSC 618" के पैरा संख्या 14, 15, 16, 17 को भी यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगा:—

*14. As rightly submitted by the appellant State, this Court, in **Lalrintluanga Sailo** (Supra) while setting aside the bail granted by the High Court therein had held that consideration on the twin conditions under Section 37 of the NDPS Act is essential by the concerned Court. It was observed:*

10. Thus, the provisions under Section 37(1)(b)(ii) of the NDPS Act and the decisions referred supra revealing the consistent view of this Court that while considering the application for bail made by an accused involved in an offence under the NDPS Act a liberal approach ignoring the mandate under Section 37 of the NDPS Act is impermissible. Recording a finding mandated under Section 37 of the NDPS Act, which is sine qua non for granting bail to an accused under the NDPS Act cannot be avoided while passing orders on such applications.”

15. *To the similar effect, this Court in **State by the Inspector of***

Police v. B. Ramu reiterated that satisfaction with the conditions laid down under Section 37 of the NDPS Act is mandatory while entertaining a prayer for bail involving commercial quantity of narcotic drugs. [See also: **Ajay Kumar Singh alias Pappu (Supra)**]

16. In similar circumstances, this Court in **Union of India v. Namdeo Ashruba Nakade** observed that the mandatory nature of Section 37 cannot be dispensed with:

“12. Prima facie this Court is of the opinion that the Respondent-accused is involved in drug trafficking in an organized manner. Consequently, no case for dispensing with mandatory requirement of Section 37 of the NDPS Act is made out in the present matter.

13. Moreover, this Court is of the view that as the accused has been charged with offences punishable with ten to twenty years rigorous imprisonment, it cannot be said that the Respondent has been incarcerated for an unreasonably long time.”

17. Keeping in view the above expositions of law, we now proceed to examine the impugned order. The abovementioned decisions of this Court display the consistent view that when it comes to cases involving commercial quantity of narcotics, the mandatory requirements of Section 37 ought to be considered. It is not in dispute that the case at hand, involves commercial quantity. In such a scenario, consideration and reference to the twin conditions enumerated under Section 37 of the NDPS Act was mandatory. Upon a bare perusal of the impugned order, it is evident that there has been no consideration at all by the High Court on the twin conditions. In such a scenario, the impugned order cannot be sustained in the eyes of law.

उपरोक्त विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा में पाये गये मादक पदार्थ के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का अधिकारी तभी माना जा सकता है, जब उसके विरुद्ध कोई अपराध प्रथमदृष्टया नहीं बनता हो। इस प्रकरण में अफीम का वजन 4 किलो 500 ग्राम बताया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा का है।

प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा के मादक पदार्थ की आपूर्ति करने के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अत्यंत गंभीर किस्म का है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रायसिंह उर्फ रामू बंजारा पुत्र बिहारी लाल बंजारा** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

35/AKSHAY KUMAR PAREEK/P.A.